

भाग एक : अर्थव्यवस्था – समीक्षा और संभावनाएं

I

मूल्यांकन और संभावनाएं

1.1 2020-21(अप्रैल-मार्च) की दूसरी तिमाही का बड़ा हिस्सा निकल चुका पर 210 देशों को अपने घातक आगोश में ले चुके कोविड -19 की छाया पृथ्वी पर अभी भी मँडरा रही है। महामारी विनाश के पदचिह्न छोड़ते आगे बढ़ रही है- रिपोर्ट जारी होने के समय तक दुनिया भर में 2.25 करोड़ पुष्ट (कन्फर्म्ड) मामलों (20 अगस्त 2020 के अनुसार) में से 7.90 लाख जिंदगियां यह निगल चुकी है, सक्रिय (एक्टिव) संक्रमण 73.59 लाख हैं और बढ़े जा रहे हैं। इसने मानव समाज को एक अनदेखे एकांतवास में धकेल दिया है, दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों पर विराम लगाया और रोजगार व आय को मटियामेट कर डाला है। राहत के प्रारंभिक अनंतिम संकेतों – परिचालन की शब्दावली में 'नई कोपलों'- पर, दमघोटू सामाजिक दूरी/मास्कों/सैनिटाइजरो तथा 'लॉकडाउन सिंड्रोम' से क्लान्त लोग अपने जीवन व जीविका पर नियंत्रण पाने की आतुरता में अलग-अलग पैमाने पर अपने पंख फैला रहे हैं। कई देशों में, संक्रमणों व मृत्यु की एक नई लहर के चलते फिर से कंटेनमेंट प्रक्रियाओं का शिकंजा कसने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यह पता लगाना मुश्किल है कि वायरस की पहली लहर और तेज हुई है या यह दूसरी लहर की चपेट है।

1.2 कोविड-19 ने भारत पर भी प्रबल आघात किया है। हाल तक को लें तो, रिपोर्ट हुए सभी मामलों में से आधे छह नगरों – मुंबई; दिल्ली, अहमदाबाद; चेन्नई; पुणे और कोलकाता – से हैं। तथापि, इधर कुछ हफ्तों में, इससे नीचे की पंक्ति में आने वाले नगरों/शहरों में इसकी रेखा ऊपर गई है तथा वायरस और

आगे भीतरी प्रदेशों में घुस रहा है। दूसरों के मुकाबले भारत ने तुरंत और ताकत से कदम उठाते हुए 25 मार्च से दो महीनों की राष्ट्र-व्यापी तालाबंदी (लॉकडाउन) की। 30 जनवरी को रिपोर्ट हुए पहले मामले एवं 12 मार्च को पहली मृत्यु से लॉक डाउन के तीन दिनों बाद तक 1000 से कुछ कम पुष्ट (कन्फर्म्ड) मामलों और 19 मौतों को लें तो गति अपेक्षाकृत धीमी थी। मध्य-मई तक महामारी ने पकड़ बना ली थी; चीन को लांघते हुए पुष्ट मामले 85,000 से अधिक हो गए। जुलाई के अंत तक जब अनलॉक 3.0 शुरू होने वाला था, 35,747 मौतों के साथ पुष्ट मामले 16.50 लाख को छू रहे थे जो बाद में (20 अगस्त 2020 के अनुसार) बढ़कर क्रमशः 53,866 मृत्यु और 28.36 लाख तक पहुँच गए।

1.3 भारत के अनुभव ने आशा तथा मानवता व इसकी सेवा में लगी संस्थाओं के अजेय चरित्र में एक सहज विश्वास को भी जन्म दिया है। स्वास्थ्य की बुनियादी व्यवस्था में बड़ी कमियों के बावजूद, भारत में मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम में से एक (20 अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार, 3.5 प्रतिशत के वैश्विक औसत की तुलना में 1.9 प्रतिशत) है। जाँच, क्लिनिकल प्रबंध और अस्पताल सहायता बढ़ाई जा रही है। स्वस्थ होने की दर 70 प्रतिशत के निकट पहुँच रही है और इसमें वृद्धि जारी है। देश के सामने ये चुनौतियां हैं: इस वक्र (कर्व) को सपाट करना, रोजगार की बहाली विशेषतः विस्थापित प्रवासियों के लिए, आपूर्ति शृंखलाओं का पुनर्निर्माण, त्रस्त अर्थव्यवस्था की मरम्मत और पुनरुत्थान तथा सामान्य जीवन की ओर वापसी। व्यापक तौर पर यह

\* यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई-जून है, लेकिन कई चरों से संबंधित आंकड़े वित्तीय वर्ष, अर्थात् अप्रैल-मार्च के आधार पर उपलब्ध होते हैं और इसलिए आंकड़ों का विश्लेषण वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाता है। उपलब्धता के अनुसार, मार्च 2020 के बाद के आंकड़े शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की गई है। विश्लेषण के प्रयोजन से तथा नीतियों का उचित परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए इस रिपोर्ट में आवश्यकतानुसार पिछले वर्षों के तथा भावी अवधि के संदर्भ भी दिए गए हैं।

माना जा रहा है कि सभी हितधारकों के बीच घनिष्ठ समन्वय द्वारा ही भारत के लोग इस पुनरुत्थान का स्वरूप निर्धारित कर सकेंगे। आगे की राह, जहाँ अभी भी बड़ी अनिश्चितता से ढँकी हुई है, वहीं विगत वर्ष के अनुभव के पन्ने पलटने से इस संकल्प को बल मिल सकता है तथा 2020-21 व उसके बाद मध्यावधि में हमारे सम्मुख उपस्थित चुनौतियों से निपटने के लिए साहस व संसाधनों को जुटाया जा सकता है।

### 2019-20 के अनुभव का आकलन

1.4 मुड़कर देखने पर, 2019 के वैश्विक घटनाक्रम में गहन चिंतन के कई पाठ हैं जिनके भारत व दूसरी सभी अर्थव्यवस्थाओं की संभावनाओं के लिए भी निहितार्थ हैं। यह अब स्पष्ट है कि 2019 की गिरावट में वैश्विक अर्थव्यवस्था उन विखंडनकारी घटनाओं को दरकिनार करते हुए आपस में फिर से जुड़ी जो गत वर्ष, घटकों के विकास मानचित्र में अंतर का संकेत देती प्रतीत हो रही थी। ध्यान देने बात है कि, विकसित अर्थव्यवस्थाओं (ईई) की तुलना में उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में शिथिलता अधिक स्पष्ट थी। वर्ष के दौरान, वृद्धि की गति में कमजोरी, भौगोलिक रूप से, अधिकाधिक व्यापक होती गई जिससे भारत समेत अलग-अलग देशों को बच पाने का कोई रास्ता नहीं था। वैश्विक शिथिलता के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तरों पर औद्योगिक उत्पादन, व्यापार व निवेश में गिरावट भी आई क्योंकि निवेश अधिक व्यापार वाले मध्यवर्ती व पूँजीगत वस्तुओं में केंद्रित है। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र में व्यापार संबंधी तनावों ने करोबारी मिज़ाज को चोट पहुँचाई। ईएमई में गिरावट से वैश्विक आयात की कमजोरी पर बड़ा असर पड़ा। फलतः, इन शक्तियों ने उस निर्यात वृद्धि को घटाया जो आयात से जुड़ी है तथा वैश्विक आपूर्ति शृंखला की स्थिति पर काफी निर्भर करती है। कुछ समय के लिए, जब विनिर्माण का इंजन धीमा पड़ा तब सर्विसेज़ मजबूती से बनी रहीं और इसने उपभोक्ता विश्वास को सहारा देने में सहायता की, लेकिन आगे चलकर वैश्विक गिरावट की भवितव्यता हावी हो गई।

1.5 इन प्रतिकूलताओं के बावजूद, वर्ष के अंतिम महीनों की ओर, ऐसे कुछ संकेत उभरे मानो यह सुस्ती अपने उस

अंतिम बिंदु पर आ रही हो जिसके बाद हालात सुधरें। कुछ देशों में राजकोषीय प्रोत्साहन से समर्थित मौद्रिक नीति के उदारीकरण के 2019 के उत्तरार्ध में जारी रहने से यह प्रत्याशा बढ़ी कि 2020 की शुरुआत में वैश्विक गतिविधि में सुधार हो सकता है। वास्तव में, चौथी तिमाही (अक्टूबर – दिसंबर 2019) के उच्च आवृत्ति संकेतकों ने बताया कि गति सुस्ती से स्थिर हो रही है। एकबारगी होने वाले कारक, जिनसे वैश्विक विनिर्माण प्रभावित हुआ था –आटो क्षेत्र के लिए नए उत्सर्जन मानक; स्टॉक का जमा होना – कमजोर पड़ते प्रतीत हुए। कारोबारी मिज़ाज और विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) की गिरावट थमी, विश्व व्यापार वृद्धि अपने न्यूनतम बिंदु से सुधार की ओर बढ़ती प्रतीत हुई और सेवा क्षेत्र के पीएमआई विस्तारी क्षेत्र में रहे।

1.6 फाइनेंस का चैनल भी अपना काम कर रहा था और, विश्वास के चैनल से जुड़कर इसने वैश्विक प्रभावों को विस्तार दिया। पहले बताए गए वास्तविक क्षेत्र के चैनलों से आ रही सकारात्मक धाराओं ने प्रारंभ में वित्तीय बाजारों को बल दिया, और व्यापारिक युद्धों के भय को कम किया तथा तथा एक दृढ़ ब्रेकिज़ट ने जोखिम के लिए निवेशकों की भूख बढ़ाई। इक्विटी कीमतों में संतुलन फिर से आता प्रतीत हुआ, सरकारी बॉण्ड प्रतिफल घटे और पोर्टफोलियो प्रवाह ईएमई की ओर लौटे। सितंबर 2019 और जनवरी 2020 की शुरुआत के बीच मुद्रा की चाल से जोखिम के मनोभावों की सामान्य मजबूती का संकेत मिला। इस प्रकार महामारी के फैलने के पहले वित्तीय स्थितियां सभी ईई और ईएमई में व्यापक तौर पर उदार एवं हल्के समुत्थान के अनुकूल हो चली थीं।

1.7 2019 के अंत में कोविड-19 की शुरुआत के साथ वित्त व विश्वास के चैनलों ने संचरण को हठात् उलट दिया। वित्तीय बाजार ठिठक गए, वित्तीय संस्थाएं बैलेंस शीट की क्षति के निर्मम आघातों की तैयारी करने लगी, घोर जोखिम-विमुखता प्रारंभ हुई और जब आय का प्रवाह, विशेषतः कवचहीनों के लिए, थमने लगा तो घर और कारोबार दोनों ने समान रूप से नकद की ओर दौड़ लगाई। कोविड-19 वैश्विक एकीकरण के नकारात्मक पक्ष को सामने ला रहा था। नतीजा, 2019 में 2.9 की वैश्विक

वृद्धि 2009 के बाद से सबसे धीमी रही। वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद से भारत की न्यूनतम सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि भी वर्ष 2019-20 (अप्रैल-मार्च) में रही। उपर्युक्त असरदार वैश्विक घटनाक्रमों के बीच, 2019 की दूसरी तिमाही से भारतीय अर्थव्यवस्था ऑटोमोबाइल व रीयल इस्टेट सेक्टर में ढलान तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) उद्यमों में कष्ट की छटपटाहट जैसे विशिष्ट घरेलू कारकों का सामना कर रही थी।

1.8 घरेलू घटनाक्रमों की ओर मुड़ें तो, गत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट ने एक अस्तित्ववादी प्रश्न रखा था: हमारा सामना किसी सॉफ्ट पैच (अल्पावधि सुस्ती) से है या किसी चक्रीय अधोगति से या फिर संरचनागत धीमेपन से? एक ओर जहाँ धीमेपन की गुत्थी सुलझाने के लिए आँकड़ों की प्रतीक्षा हो रही थी, वहीं आने वाली हर तिमाही के साथ गति हास को गहराते देखकर सॉफ्ट पैच को खारिज कर दिया गया। मुड़कर देखें तो, जीएफसी के बाद से भारत अंग्रेजी वर्णमाला के वी(V)-आकार के समुत्थान से गुजरा था, लेकिन प्रोत्साहन (स्टीमुलस)-चालित यह उठान कायम नहीं रह पाई: औसत जीडीपी वृद्धि 2009-11 के 8.2 प्रतिशत से घटकर 2011-13 में 5.3 पर आ गई थी। 2013-14 से एक चक्रीय उठान ने पैर जमाए और यह स्वातंत्र्योत्तर कालखंड में दीर्घतम में से एक सिद्ध हुआ जो 2016-17 में 8.3 प्रतिशत पर पहुँचा। हालांकि, 2018 में प्रारंभ हुई चक्रीय वैश्विक गिरावट के पहले भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि ने 2017 में सुस्ती के संकेत दिए थे। धीमी पड़ रही गति के बावजूद, अनुकूल सांख्यिकीय आधार के प्रभावों ने 2017-18 की दूसरी छमाही में चक्रीय अधोगति के प्रारंभ को टाल दिया। तथापि, आगे चल कर, 2018-19 की पहली तिमाही से भारत वैश्विक शिथिलता का हिस्सा बन गया और अगली 8 तिमाहियों में लगातार गति खोता हुआ 2019-20 की चौथी तिमाही में 3.1 प्रतिशत पर पहुँच गया जो 2011-12 पर आधारित राष्ट्रीय लेखा शृंखला में निम्नतम है।

1.9 इस प्रकार कोविड-19 की शुरुआत होने तक, भारत के वृद्धि पथ की सुस्ती में वैश्विक व घरेलू दोनों प्रकार की चक्रीय शक्तियों का प्रभाव दिख रहा था। वैश्विक चालकों में पहले से नरम बाह्य मांग, विश्व के कई हिस्सों में ऑटोमोबाइल उत्सर्जन के नए मानक, प्रणालीबद्ध ईएमई के किसी समूह में विशेष प्रकार के कारकों के चलते कमजोर समष्टि-आर्थिक स्थितियाँ, व्यापारिक तनावों व वृहत्तर वैश्विक व्यापार नीति अनिश्चितता, चीन में मंदी व नो-डील ब्रेकिजट की संभावना शामिल हैं। घरेलू कारक पहले वास्तविक क्षेत्र में स्टॉक की अधिकता के रूप में आए और इसके बाद व्यापार की प्रतिकूल शर्तों के चलते ग्रामीण मांग में सूखा, 2018-19 की चौथी तिमाही से सकल स्थिर पूँजी निर्माण में कमी तथा 2019-20 की पहली तिमाही से पण्य निर्यात और 2019-20 की दूसरी तिमाही से आयात में कमी आई। हास के इस दौर (2018-19 की चौथी तिमाही से 2019-20 की चौथी तिमाही) को और हवा मिली अटपटी घटनाओं से जैसे वाणिज्यिक वाहनों के लिए ऑटो उत्सर्जन मानक/एक्सल मानक और एनबीएफसी क्षेत्र में ऋण संबंधी घटनाएं।

1.10 वृद्धि में कमी की इस अंतर्निहित चक्रीय प्रकृति को समय रहते समझते हुए मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी 2019 के प्रारंभ से ही कई नीति दर कटौतियाँ करते हुए फरवरी 2020 तक कुल 135 आधार अंक कम किए; नीति का रुख नपी-तुली सख्ती से बदलकर पहले तटस्थ और फिर उदार किया; और 2019-20 की दूसरी तिमाही से प्रणाली में भरपूर चलनिधि डाली। भारत में सामान्यतः अंतराल से और अपूर्ण रूप से होने वाला मौद्रिक संचरण, पर्याप्त चलनिधि परिस्थितियों के तहत एवं अक्टूबर में चुनिंदा क्षेत्रों में नए कर्जों पर ब्याज दरों को बाह्य बेंचमार्क से जोड़े जाने की अनिवार्यता के कारण, वर्ष के उत्तरार्ध में, काफ़ी सुधर गया। उदाहरण के लिए, फरवरी 2019 से फरवरी 2020 के बीच, नए बैंक लोन पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) में 71 आधार अंकों की कमी आई जिसमें से 31 आधार अंक अक्टूबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच के हैं। वृद्धि के लिए सहायक

मौद्रिक नीति रुख में प्रतिचक्रिय बदलाव वर्ष की पहली छमाही में मुद्रास्फीति के नरम पड़ने के कारण था; खाद्य कीमतों के बढ़ने के कारण दिसंबर 2019 – फरवरी 2020 के बीच, हेडलाइन मुद्रास्फीति के 6 प्रतिशत के पार चली गई, फिर भी, समग्र तौर पर वर्ष के लिए इसका औसत 4.8 प्रतिशत ही रहा जो 4 प्रतिशत के लक्ष्य से कुछ ही अधिक है।

1.11 7वें वेतन आयोग निर्णय (पे कमीशन अवार्ड) के रूप में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय और वन रैंक वन पेंशन से जीडीपी को सतत सहायता मिलने के कारण 2016-17 की चौथी तिमाही से राजकोषीय नीति भी प्रतिचक्रिय हो गई थी। भारत को एशियाई देशों के समकक्ष ला देने वाले कॉरपोरेट टैक्स व्यवस्था में विशाल परिवर्तन के साथ 2019-20 की दूसरी तिमाही से राजकोषीय नीति विस्तारी हो गई। चक्र से राजस्व में पैदा हुई कमी के साथ इस राजकोषीय हलचल के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) में वर्ष के लक्ष्य से एक बड़ा विचलन पैदा किया – बजटित 3.3 प्रतिशत की तुलना में जीडीपी का 4.6 प्रतिशत – जिसके चलते संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (एफआरबीएम) अधिनियम के अंतर्गत बचाव खंड (इस्केप क्लॉज) के प्रयोग की नौबत आ गई। राजस्व में भारी कमी को देखते हुए, गत वर्षों की तरह, मुख्यतः व्यय में कमी द्वारा उप-राष्ट्रीय राजकोषीय नीति राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफएलआर) की सीमाओं में रही। तथापि स्व-स्थिरक (ऑटोमैटिक स्टेबिलाइज़र्स) ने, विशेषतः टैक्स के मोर्चे पर, एक प्रतिचक्रिय भूमिका निभाई होती। कुल मिलाकर, राज्यों व केंद्र दोनों के पास कोविड-19 से निपटने के लिए उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश जीएफसी के दौर की तुलना में काफ़ी कम थी।

1.12 2019-20 में, घरेलू मांग के निर्माण पर वापस आए तो, उपभोग तुलनात्मक रूप से दृढ़ सिद्ध हुआ। जैसा कि पहले चर्चा हुई है, अधोगति को थामा सरकारी उपभोग ने – इसके बिना, 2019-20 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 4.2 प्रतिशत के हेडलाइन से गिरकर मुश्किल से 3.3 प्रतिशत तक

आती। जीडीपी में 57 प्रतिशत हिस्से वाला निजी उपभोग, जो घरेलू मांग की आधारशिला है, समग्र स्तर पर गति की क्षति झेल गया और 2019-20 की चौथी तिमाही में जाकर घटने लगा। 2019-20 में शिथिलता के प्रमुख चालक निवेश व निर्यात थे।

1.13 स्थिर (फ़िक्सड) निवेश में सुस्ती 2011-12 से शुरू हो गई और 2018-19 की चौथी तिमाही से गहरी हो गई तथा 2019-20 की दूसरी तिमाही से संकुचन में चली गई। कॉरपोरेटों व बैंकों के तुलन पत्रों में दबाव, एनबीएफसी में चूक, हाउसहोल्ड्स की धीमी पड़ती आय वृद्धि के कारण अनबिके घरों के अंभार का बढ़ना और वैश्विक सुस्ती का मिश्रण सहज वृत्तियों (एनिमल स्पिरिट्स) पर काफ़ी हावी रहा।

1.14 वर्ष के दौरान अमेरिकी डॉलर में निर्यात में 5.1 प्रतिशत का संकुचन निर्यात की कीमतों में 4.7 प्रतिशत की गिरावट से जुड़ा है। क्षेत्रवार विश्लेषण से बहुमूल्य जानकारी निकल कर आती है। उदाहरण के लिए, एक निर्यात समूह – इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं; ड्रग्स और फर्मास्यूटिकल्स; लौह खनिज – कमज़ोर होती बाह्य मांग और देश विशेष की बाधाओं के बावजूद मजबूती से टिके रहे। इनमें से प्रत्येक में निर्यात की भारी संभावनाएं हैं, विशेषतः अंतरराष्ट्रीय परिवेश के तेजी से बदलते समीकरण में।

1.15 2019-20 में सकल आपूर्ति स्थितियों के विकास का जहाँ तक प्रश्न है, अपने रिकॉर्ड खाद्यान्न व बागबानी उत्पादन तथा कृषि अर्थव्यवस्था के लिए व्यापार की अनुकूल शर्तों वाली कृषि व संबंधित गतिविधियों ने उम्मीद जगाई। अनाज में अत्यधिक आपूर्ति के प्रबंधन की चुनौती ने मूल्य समर्थन और बफरस्टॉकिंग जैसी नीतिगत हस्तक्षेप की कमियों को उजागर किया। विरोधाभास यह है कि कृषि उत्पादों के खेतों से बाजार तक परिवहन को प्रभावित करने वाले प्रतिबंधों और कृषि आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों से मांग-आपूर्ति का असंतुलन पैदा हुआ जो वर्ष के उत्तरार्ध में कीमतों के भड़कने का कारण बना। कृषि की मार्केटिंग और बुनियादी व्यवस्थाओं में हाल में

हुए सुधारों को अगर पूर्वानुमेय व्यापार नीतियों का सहयोग मिला तो कृषि के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं और कृषि क्षेत्र को व्यापार की अंतरराष्ट्रीय शर्तों का एक्सपोजर मिलेगा तथा प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) और मूल्य वर्धन की ओर जोर बढ़ेगा।

1.16 औद्योगिक क्षेत्र में 2015-16 से एक संरचनात्मक शिथिलता शुरू हो गई है जिसका केंद्र विनिर्माण है। श्रम, भूमि व उत्पाद बाजारों में संरचनात्मक रुढ़ियों ने भारतीय विनिर्माण को विश्व के बाजारों में अप्रतिस्पर्धी और युवा परंतु अपर्याप्त कुशलता वाले श्रमिक बल में मौजूद जनसांख्यिकीय लाभ का दोहन करने में अक्षम बना दिया है। भौतिक आधार-संरचना में बड़ी कमी ने उत्पादकता और समग्र क्षमता को प्रभावित किया है। अधिक हाल में, ऊँचे लीवरेज और ऋण-शोधन संबंधी चिंताओं ने तुलन पत्रों पर दबाव बढ़ाया है जिससे दिवालिया प्रक्रियाएं चित्त होती दिख रही हैं। इसके अलावा, पहले के कुछ मुद्दे, अभी भी बोज़ बने हुए हैं जैसे जमीन अधिग्रहण में विलंब, पर्यावरणीय चिंताएं और एमएसएमई क्षेत्र में तरह-तरह की बाधाएं।

1.17 सेवा क्षेत्र पिछले तीन दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य चालक रहा है। 2019-20 तक, इसने दृढ़ता और उत्पादकता दिखाई थी; तथापि घरेलू तथा वैश्विक दोनों स्तरों पर अटपटे घटनाक्रम—एक एयरलाइन का बैठ जाना; वित्तीय क्षेत्र दबाव; रुकी हुई निर्माण परियोजनाएं; टेलीकॉम में राजस्व से जुड़े मुद्दे; मंद विदेश व्यापार से बाधित बंदरगाह (पोर्ट) गतिविधि; कोयला उत्पादन में क्षय से रेलवे के माल यातायात का प्रभावित होना—सकल मांग में सुस्ती के साथ मिलकर इस क्षेत्र के उत्पाद को दो दशकों में इसकी न्यूनतम वृद्धि तक घसीट ले गए। गत वर्ष सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन में प्रत्येक उप-क्षेत्र की विशिष्ट संरचनात्मक बाधाओं का उदय दिखता है। तथापि, सेवा निर्यात ने पण्य निर्यात को पछाड़ा है एवं 2019-20 में वैश्विक हिस्सा बनाए रखा है और इसमें आगे रहने में सॉफ्टवेयर ने अहम भूमिका निभाई। क्लाउड कंप्यूटिंग और

डिजीटलीकरण से प्राप्त स्वचालन (ऑटोमेशन) और क्षमता में लाभ की ओर निवेश को मोड़कर तथा वैश्विक कंपनियों से नए गठबंधन से भी आईटी की बड़ी भारतीय कंपनियां लाभान्वित हो सकती हैं।

1.18 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक के क्षेत्राधिकार वाले वित्तीय बाजार के विभिन्न वर्गों को विकसित करने के कई प्रयास किए गए। विदेशी मुद्रा बाजार में, पहुँच को प्रोत्साहित करने, ऑन शोर और ऑफ शोर गतिविधि के वर्गीकरण को पाटने, विनियमों के समग्र युक्तिकरण के अंतर्गत हेजिंग व्यवस्था के सरलीकरण और सिद्धांत – आधारित विनियमाकीय ढाँचे में कारोबारी सुगमता में वृद्धि पर ध्यान दिया गया। ऋण बाजार में, विदेशी मुद्रा पोर्टफोलियो निवेश को उदार बनाने के अन्य उपायों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट प्रतिभूतियां पूर्णतः अभिगम्य मार्ग (एफएआर) के तहत अनिवासियों के लिए खोली गईं। लागत व जोखिम को कम करने के उद्देश्य के तारतम्य में केंद्र व राज्य सरकारों के बाजार उधारी कार्यक्रम संपन्न किए गए। चलनिधि (लिक्विडिटी) में वृद्धि, निवेशक आधार के विस्तार और ऋण प्रबंधन रणनीतियों के उन्नयन द्वारा ऋण बाजार का विकास किया गया। मुद्रा बाजार में, एक संशोधित चलनिधि प्रबंधन का ढाँचा लाया गया जिससे रिज़र्व बैंक को चलनिधि की परिस्थितियों को पारंपरिक व गैर-पारंपरिक साधनों का प्रयोग करते हुए सक्रियता से मैनेज करने का अधिकार हो। उल्लेखनीय है, कि 2018-19 में आरंभ किए गए करेंसी स्वैप के अलावा रिज़र्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन के तरकश में दीर्घावधि रिपो परिचालन और विशेष ओएमओ जोड़े गए।

1.19 विनियामकीय और पर्यवेक्षी क्षेत्र में, वित्तीय मध्यस्थों को मजबूत करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के कई कदम उठाए गए। ये प्रयास अर्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए जो प्रणालीगत तनाव परीक्षणों, वित्तीय नेटवर्क विश्लेषण और समूचे विनियामक फ्रेमवर्क के आकलन के माध्यम से वित्तीय स्थिरता के जोखिम का आकलन करते

हुए वित्तीय प्रणाली पर निगरानी रखती है। बैंकिंग सिस्टम में, विवेकसम्मत विनियामकीय ढाँचों को वैश्विक मानकों के तारतम्य में लाने के चल रहे प्रयास आगे बढ़ाए गए। कॉरपोरेट गवर्नेंस, जोखिम प्रबंधन और ऋण सुपुर्दगी, में सुधार के साथ, तकनीक का भरपूर उपयोग करते हुए साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया। दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विगत प्रयासों के परिणाम आते प्रतीत हो रहे थे: मार्च 2018 में 11.5 प्रतिशत के शिखर पर पहुँचने के बाद, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के सकल अनर्जक आस्तियों(जीएनपीए) के अनुपात में कमी प्रारंभ हुई जो मार्च 2020 के अंत तक 8.5 प्रतिशत तक आ गई। एससीबी का प्रावधान कवरेज अनुपात लगातार तीसरे वर्ष बेहतर होकर मार्च 2020 में 65.4 प्रतिशत पर पहुँच गया।

1.20 एससीबी के जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) बेहतर होकर मार्च 2020 में 14.8 प्रतिशत ( एक वर्ष पूर्व 14.3 प्रतिशत) हो गया। कारण (ट्रिगर) आधारित पर्यवेक्षी कार्रवाई की समीक्षा, ₹100 करोड़ या उससे अधिक की जमाराशि वाले शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए प्रबंधन बोर्ड के गठन, यूसीबी के एकल और समूह उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर मानकों के युक्तिकरण तथा केरल में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के समामेलन और यूसीबी के लिए केंद्रीय फ्रॉड रजिस्टरी (सीएफआर) के विकास द्वारा सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के विनियामकीय व पर्यवेक्षी ढाँचे को मजबूत बनाने के कदम उठाए गए। आगे, बैंकिंग रेग्यूलेशन ऐक्ट 1949 की कुछ धाराओं के संशोधन द्वारा रिजर्व बैंक की विनियामकीय शक्तियों को मजबूत करते हुए इसके विनियामकीय अधिकार में सहकारी बैंकों के कार्य के कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों को लाया गया।

1.21 बैंकिंग क्षेत्र से तारतम्य के लिए एनबीएफसी के चलनिधि जोखिम प्रबंधन में संशोधन किए गए और इसके आस्त-देयता प्रबंधन ढाँचे को मजबूत बनाया गया। रिजर्व बैंक

को आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के विनियमन और एनबीएफसी पर व्यापक विनियामकीय अधिकार दिए गए। इसके साथ तकनीक-युक्त ग्राहक सेवाओं, ग्राहक सुरक्षा और फ्रॉड की धर-पकड़ पर भी कार्य चलते रहे।

1.22 वित्तीय समावेश के कार्य को आगे बढ़ाते हुए वित्तीय राष्ट्रीय वित्तीय समावेश कार्यनीति (नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इनक्लूजन), 2019-2024 जारी की गई और डिजिटल पेमेंट परितंत्र को गहरे ले जाने के कदम उठाए गए। पुनश्च, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के प्रयास भी तेज किए गए। गाँवों में बैंकिंग सेवाएं देने की योजना के तहत, 30 सितंबर 2019 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 2,000 से कम की आबादी वाले चिह्नित गाँवों के 99.2 प्रतिशत और 5,000 से अधिक की आबादी वाले चिह्नित गाँवों के 94.4 प्रतिशत में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

1.23 भुगतान व निपटान प्रणाली विज्ञान 2019-21 की प्रेरणा से किफायती लागत में उपयोग-सुगम प्लेटफॉर्मों की उपलब्धता पर ध्यान देते हुए सक्षम एवं सुरक्षित भुगतान व निपटान प्रणाली विकसित करने के प्रयास किए गए। रिजर्व बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) और रूपे कार्डों की पहुँच को विश्व भर में विस्तार देने की दिशा में कार्य किए। डिजिटल पेमेंट उपयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन तैयार किए गए। ग्राहक सेवा में सुधार में ये चीजें शामिल हैं : 24x7x365 आधार पर एनईएफटी की उपलब्धता, आरटीजीएस के कार्य के घंटों में वृद्धि, कार्डों पर ई-मेंडेट, प्रीपेड पेमेंट इनस्ट्रूमेंट (पीपीआई) और यूपीआई, भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) के अंतर्गत बिलर वर्गों का विस्तार और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) प्रणाली के उपयोग में वृद्धि। नकदीतर खुदरा भुगतानों की कुल मात्रा में डिजिटल लेन-देन का अंश गत वर्ष के 95.4 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 97.0 प्रतिशत हो गया। मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणालियों (सीवीपीएस) के प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) तथा मुद्रा प्रबंध के कार्यों का रिजर्व

बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के साथ एकीकरण द्वारा मुद्रा प्रबंध को सुदृढ़ किया गया।

1.24 पृष्ठ पलटकर अस्तित्ववादी प्रश्न पर आते हैं, उपलब्ध सभी साक्ष्य भारत में चक्रीय अधोगति की ओर ही संकेत करते प्रतीत हुए जो हाल के इतिहास में सबसे बड़े विस्तारों में से एक के बाद 2018-19 और 2019-20 में विश्व भर में एक ही समय घटित हुआ। 2019-20 के अंत की ओर चक्र का हासमान चरण पहुँच कर अभी संभलता कि कोविड-19 आ धमका और पूरे आख्यान की धज्जियां उड़ा दी। आज आने वाले कल की संभावनाओं के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं और मालूम नहीं कि भविष्य कैसा होगा। इस कयास में ये बातें शामिल हैं: अवरुद्ध माँग के बाधामुक्त होने पर ज्वालामुखीय विस्फोट के कारण वी (V) आकार की वापसी जो नए विस्तार के बढ़ते मार्ग की जमीन तैयार करता है; विविध प्रकार की मध्यवर्ती पुनरावृत्तियों से होकर; व्यवहार व जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के चलते घटित संरचनात्मक गतिहीनता तक। इस गंभीर बिंदु पर, यह देखना उचित रहेगा कि आगे 2020-21 में और उसके बाद क्या है।

### 2020-21 के लिए संभावनाएं

1.25 मार्च में उँचाई से गिरने और 2020 की पहली छमाही में ऐसे संकुचन, जो व्यापक तौर पर महामंदी और जीएफसी जैसा गहरा व उससे भी विनाशकारी माना जाता है, से गुजरने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था तेज गिरावट के चंगुल से बाहर आने लगी है। जैसे-जैसे अलग-अलग स्तरों पर अर्थव्यवस्थाओं की अनलॉकिंग शुरू हो रही है और अवरुद्ध मांग को मुक्त (रिलीज) किया जा रहा है, 2020 की तीसरी तिमाही में गतिविधि अपने न्यूनतम बिंदु से सुधार की ओर बढ़ने लगी है। वैसे, कंटेनमेंट और सामाजिक दूरी में रियायतें हिचकिचाहट भरी रही हैं और कई देशों में संक्रमण व मृत्यु की नई लहर के कारण रुक गई हैं। सब ओर, आपूर्ति शृंखला और उत्पादन संरचनाएं बिखर गई हैं और आपूर्ति का यह आघात पण्य, विशेषतः धातुओं, की कीमतों में प्रतिबिंबित हो रहा है। महामारी की अधिक बड़ी मार मांग (डिमांड) पर पड़ी है। स्वनिर्णय

से बाहर अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतें तो तेजी से बढ़ी हैं, जबकि कई स्वनिर्णयगत वस्तुएं तो लेन-देन से बाहर हो गई हैं। जोखिम-विमुखता की अधिकता के बीच कारोबार और गृहस्थ (हाउसहोल्डस) को एहतियाती बचत की प्रवृत्ति ने जकड़ लिया है और निवेश की भूख हवा हो गई है। महामारी ने नई असमताओं को भी उजागर किया है –सफ़ेदपोश कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं जबकि अत्यावश्यक श्रमिकों को साइट पर काम करना पड़ता है जहाँ संक्रमण का जोखिम है। आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी), होटल और रेस्टॉरेंट, एयरलाइन्स और पर्यटन जैसे कुछ कार्यक्षेत्रों में रोजगार की हानि अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक गंभीर है। निर्धनतम पर कठोरतम आघात हुआ है।

1.26 नीति का अभूतपूर्व रेस्पॉन्स कोविड-19 के अनुभव की एक प्रमुख विशेषता रही है। आईएमएफ के अनुसार, जी20 देशों में कुल वित्तीय सहायता (स्टीमुल्स) पैकेज (चलनिधि व राजकोषीय उपाय) का औसत जीडीपी का 12.1 प्रतिशत रहा है (ईएमई के मामले में जीडीपी का 5.1 प्रतिशत और ईई के मामले में 19.8 प्रतिशत)। नीति की जवाबी कार्रवाई ने वित्तीय बाजारों को शांत किया और यह आस्तित्व मूल्य मुद्रास्फीति का कारण भी बना जो संबंधित आर्थिक गतिविधि से असंगत था, वित्तीय संस्थाओं और कॉरपोरेशनों को डूबने से बचाया तथा हाउसहोल्ड आय को कुछ सुरक्षा दी। राजकोषीय नियमों को अलग रख दिया गया है। ईमान की प्रहरी मुद्रास्फीति की लगाम से बाहर केंद्रीय बैंक तुलन पत्रों (बैलेंस शीट्स) के अतुलनीय विस्तार का निहितार्थ है कि चुकौती की बाध्यताएं लगभग नदारद होने की स्थिति में, सार्वजनिक व निजी दोनों ऋणों पर, ब्याज दरों को कम रखने जैसे कार्य द्वारा वे संभवतः चुपचाप स्टीमुल्स को फाइनेंस कर रहे हों। नतीजा यह है कि सरकार और केंद्रीय बैंक उत्तरोत्तर संसंधान आबंटन की भूमिका में आ रहे हैं जो पारंपरिक रूप से बाजारों ने किया है। वायरस पर विजय पाने और वैक्सीन पाए जाने के बाद जब तक ये प्राधिकारी समय से एवं विश्वसनीय ढंग से नहीं निकल जाते इसके अनिवार्यतः राजनीतिक परिणाम

हो सकते हैं। इन घटनाक्रमों की वृष्टि-छाया में, मुख्य वित्तीय मध्यवर्तियों के रूप में बैंक व बैंकेतर वित्तीय इकाइयों की भूमिका क्षीण पड़ी है जबकि पूंजी व बॉण्ड बाजार हावी हो गए हैं। इन सब में, सामान्य जोखिमों को पृष्ठभूमि में डाल दिया गया है, जहाँ वे खौफनाक ढंग से रूप बदल रहे होंगे – राजकोषीय प्रभुत्व; मुद्रा स्फीति; लीवरेज; बाजार विफलता। इस बीच, संकट अवसर प्रस्तुत कर रहा है और भविष्य का आकार इस पर निर्भर करेगा कि इनका उपयोग कितनी अच्छी तरह होता है।

1.27 वैश्विक आर्थिक गतिविधि कोविड-पूर्व के स्तरों से काफी नीचे है। 2020 की पहली तिमाही में ईई में जीडीपी 1.2-13.6 प्रतिशत की रेंज में संकुचित हुई; ईएमई में वृद्धि 4.5 प्रतिशत और (-) 6.8 प्रतिशत के बीच रही। जीडीपी के प्रारंभिक आँकड़े और उच्च आवृत्ति वाले संकेतक बताते हैं कि दूसरी तिमाही में भी संकुचन जबर्दस्त रहे और तीसरी तिमाही का अल्पावधि परिदृश्य धुँधला है क्योंकि उच्च बारंबारता वाले संकेतक मिली-जुली तसवीर पेश कर रहे हैं। वैश्विक विनिर्माण पीएमआई 5-माह के संकुचन से बाहर आकर जुलाई में 50.3 तक चढ़ा। वैश्विक सेवा पीएमआई भी वृद्धि दर्ज करते हुए जुलाई में 50.5 पर आया। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, पण्य व्यापार पहली तिमाही में वर्ष-दर-वर्ष 3.0 प्रतिशत सिकुड़ा, परंतु प्रारंभिक आकलन दूसरी तिमाही में 18.5 प्रतिशत की गिरावट बताते हैं। वैश्विक प्राथमिक पण्य कीमतें (आईएमएफ द्वारा जारी) वर्ष की पहली छमाही में संकुचित होकर दिसंबर 2019 की तुलना में जुलाई 2020 में 13.4 प्रतिशत घटीं। मार्च और अप्रैल में तीव्र गिरावट के बाद ओपीईसी प्लस देशों द्वारा आपूर्ति में कटौती और लॉकडाउन के प्रतिबंधों में क्रमशः ढील के बाद कच्चे तेल की कीमतें सुधरी – ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत अप्रैल 2020 के \$23.3 प्रति बैरल से बढ़कर जुलाई में औसतन \$42.8 प्रति बैरल पर रही। भारी अनिश्चितता में सुरक्षा की ओर पलायन के कारण दिसंबर 2019

की तुलना में जुलाई 2020 में 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ स्वर्ण कीमतों का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। धातुओं के अलावा, आपूर्ति में व्यवधानों के कारण अप्रैल से खाद्य कीमतें बढ़ी हैं। इन कारकों ने मुद्रास्फीति के परिणामों को भी प्रभावित किया है। ईई में, माँग में बड़ी सुस्ती ने मुद्रास्फीति को मौन रखा है, जबकि कई ईएमई में, खाद्य कीमतों में आई उछाल का नतीजा हाल के इतिहास की तुलना में हेडलाइन मुद्रास्फीति के मजबूत होने में दिखा।

1.28 अपने अद्यतन अपडेट (जून 2020) में, आईएमएफ ने 2020 के लिए -4.9 प्रतिशत वैश्विक वृद्धि का अनुमान लगाया जिसमें पहली छमाही में आर्थिक गतिविधि पर बड़ा ऋणात्मक प्रभाव और पहले की गई प्रत्याशा से अधिक क्रमिक सुधार शामिल है। 2020-21 के लिए भारत की वृद्धि (-) 4.5 प्रतिशत अनुमानित है। ओईसीडी द्वारा 10 जून 2020 के अनुमान दो परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं— एक आघात और दुहरा आघात<sup>1</sup>—दूसरे में तीव्र संक्रमण की एक द्वितीय लहर 2020 में बाद में उभरती है। एक आघात परिदृश्य में वैश्विक वृद्धि (-) 6.0 प्रतिशत और दुहरे आघातके परिदृश्य में (-) 7.6 प्रतिशत अनुमानित है [2020-21 में भारत की वृद्धि क्रमशः (-) 3.7 प्रतिशत और (-) 7.3 प्रतिशत पर अनुमानित है]। ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स में विश्व बैंक ने आठ दशकों में सबसे गहरी वैश्विक मंदी 2020 में होने की बात कही है जो अभूतपूर्व नीतिगत अवलंब के बावजूद 2009 की वैश्विक मंदी से लगभग तीन गुना अधिक होगी। कुछ घटनाक्रम संकेत दे रहे हैं कि संभव है 2020 की तीसरी तिमाही में विश्व व्यापार का संकुचन अपने निम्नतम बिंदु पर आ रहा हो जहाँ से इसमें सुधार हो। अंतरराष्ट्रीय हवाई माल का बड़ा हिस्सा ढोने वाली वैश्विक वाणिज्यिक उड़ानों में जनवरी और अप्रैल के बीच (-)74.0 प्रतिशत की कमी आई, पर मध्य-जून में वे 58.0 प्रतिशत बढ़ीं। ऐसा प्रतीत होता है कि पीएमआई में नए निर्यात आदेश

<sup>1</sup> एक आघात (सिंगल हिट) के परिदृश्य में प्रकोप से उबरने के लिए कंटेन्मेंट के वर्तमान उपाय पर्याप्त समझे गए हैं। दुहरे आघात (डबल हिट) के परिदृश्य में, वर्ष के अंत के पहले (अक्टूबर/नवंबर) वायरस की एक दूसरी लहर का आघात होता है जिसमें एक और व्यापक लॉकडाउन की जरूरत पड़ती है।



(एक्सपोर्ट ऑर्डर्स) के साथ जून में कंटेनर बंदरगाह प्रवाह क्षमता (पोर्ट थ्रूपुट) ने भी कुछ वापसी की है। अप्रैल 2020 में, डब्ल्यूटीओ ने एक अपेक्षाकृत आशाजनक परिदृश्य रखा जिसमें 2020 में विश्व पण्य व्यापार 13.0 प्रतिशत संकुचित होगा और एक निराशाजनक परिदृश्य जिसमें व्यापार 32.0 प्रतिशत गिरेगा। पहली और दूसरी तिमाही में संकुचन को देखते हुए, वर्ष के आशाजनक अनुमानों को पूरा करने में वर्ष के शेष हिस्से में प्रत्येक तिमाही में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि की दरकार होगी।

1.29 भारत की स्थिति देखें तो 2020-21 की पहली तिमाही (ति1:2020-21) के लिए एनएसओ के जीडीपी आकलन 31 अगस्त को जारी किए जाने हैं। इस बीच, अब तक जो उच्च बारंबरता वाले संकेतक आए हैं वे गतिविधियों में ऐसी कमी इंगित करते हैं, जैसी इतिहास में पहले नहीं देखी गई। साथ ही, देश के कई भागों में तालाबंदी (लॉकडाउन) में छूट के बाद मई और जून में दिखाई देनेवाली हल्की तेजी, जुलाई और अगस्त में कमजोर पड़ गई प्रतीत होती है, जो संकेत देते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में संकुचन संभवतः ति2 (दूसरी तिमाही) तक चलेगा। कुल ई-वे बिल निर्गम, जो घरेलू व्यापारिक गतिविधियों का संकेतक है, जून 2020 में माह-दर-माह (एम-ओ-एम) आधार पर 70.3 प्रतिशत बढ़ा, तथापि जुलाई में यह केवल 11.4 प्रतिशत माह-दर-माह बढ़ा और एक वर्ष पहले की तुलना में 7.3 प्रतिशत नीचे बना रहा। जून 2020 के दौरान अंतर्राज्य ई-वे बिल 91.3 प्रतिशत बढ़े, लेकिन जुलाई में वे केवल 15.3 प्रतिशत बढ़े। इसी प्रकार, अंतःराज्य ई-वे बिल, जो जून में 60.1 प्रतिशत (माह-दर-माह) बढ़े, जुलाई में केवल 9.1 प्रतिशत बढ़े। गूगल मोबिलिटी ट्रेंड, जो अंतर्निहित आर्थिक गतिविधि के प्रतिबिम्ब के रूप में लोगों की आवाजाही को ट्रैक करता है, जून 2020 में अपने अप्रैल और मई के स्तर से ऊपर चढ़ा। किराना और दवाओं से जुड़ी गतिशीलता (मोबिलिटी) कोविड-19-पूर्व स्तर तक पहुंच गई, जबकि फरवरी 2020 के स्तर की तुलना में खुदरा और मनोरंजन से

जुड़ी गतिशीलता 60.0 प्रतिशत के आस-पास और मार्गस्थ गतिविधि 40 प्रतिशत कम थी। तथापि, जुलाई में यह कुछ धीमी हुई और खुदरा और मनोरंजन एक तिहाई पर स्थिर रहे तथा सुपरमार्केट और फार्मेसी से जुड़ी लोगों की आवाजाही में कुछ कमी आई।

1.30 आगे, सरकारी उपभोग मांग को महामारी के प्रभाव से बचाता रहेगा, और निजी उपभोग पुनरुत्थान, जब भी यह आए, की अगुआई करेगा जिसमें स्वनिर्णय से बाहर (नॉन-डिस्क्रिशनरी) व्यय तब तक आगे बना रहेगा जब तक प्रयोज्य आय में टिकाऊ वृद्धि से स्वनिर्णयगत व्यय को गति नहीं मिल जाती। वर्ष के दौरान अब तक की समग्र मांग के एक मूल्यांकन से पता चलता है कि उपभोग पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और इसे सुधरने तथा कोविड-पूर्व गति प्राप्त करने में काफी समय लगेगा। निजी उपभोग के प्रत्येक क्षेत्र में स्वनिर्णयगत व्यय पर असर पड़ा है, विशेष रूप से यातायात सेवाएं, आतिथ्य क्षेत्र, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों में। व्यवहार-संबंधी संयम इन गतिविधियों की मांग के सामान्य होने में बाधा डाल सकते हैं। जुलाई माह के लिए रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि उपभोक्ता विश्वास सर्वकालिक निम्न स्तर पर पहुंच गया है और अधिकांश अभिमत-दाताओं ने सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार, मुद्रास्फीति और आय के बारे में निराशा जताई यद्यपि आने वाले वर्ष के लिए इसमें सुधार के संकेत हैं। शहरी उपभोक्ता मांग को और बढ़ा झटका लगा है- ति1:2020-21 में यात्री वाहन विक्रय और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति एक वर्ष पहले के स्तर का पांचवा भाग रह गई है; हवाई यात्री ट्रैफिक थम गया है। इसकी तुलना में ग्रामीण मांग की स्थिति बेहतर रही है। अंतर्निहित संकेतकों में, खरीफ बुवाई की मजबूत गति के कारण ट्रैक्टर की बिक्री जुलाई में 38.5 प्रतिशत बढ़ी, जबकि मोटरसाइकिल की बिक्री में आया संकुचन जुलाई में कम हुआ (जून में 35.2 प्रतिशत से जुलाई में 4.9 प्रतिशत)। उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में आई कमी भी जून में धनात्मक (पॉजिटिव) रही। तथापि ग्रामीण मांग में पूर्ण सुधार धीमी मजदूरी वृद्धि के कारण बाधित हो रहा

है, जो अब भी प्रवासी समस्या और संबंधित रोजगार हानि से प्रभावित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की संभावना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत बढ़ाई गई मजदूरी के साथ-साथ इनसे ग्रामीण आय को बल मिलेगा।

1.31 सरकारी उपभोग व्यय ने राहत दी है, और ब्याज भुगतान व प्रमुख सब्सिडियों को छोड़कर केंद्र सरकार का राजस्व व्यय, वर्ष की पहली तिमाही में 33.7 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि, कोविड-19 के प्रभाव को कम करने की जरूरत के कारण सरकारी वित्त पर दबाव पड़ा है और जिससे सकल मांग को सपोर्ट करते रहने की गुंजाइश काफी कम हो सकती है। राज्य वित्त के मामले में, इस गुंजाइश को इतना निचोड़े जाने की संभावना है कि वृद्धि-प्रदान करने वाले पूंजीगत व्यय में कटौती किया जाना बिल्कुल संभावित प्रतीत हो रहा है। राजकोषीय नीति का भावी पथ काफी हद तक कर्ज के बड़े अंबार (ओवरहैंग) तथा महामारी के दौरान बनने वाली आकस्मिक देयताओं द्वारा निर्धारित होने की संभावना है। एक विश्ववसनीय समेकन योजना, जिसमें बजाय अपरिहार्य को खींचने टालने के, ऋण और घाटे के स्तर को कम करने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों को निर्दिष्ट किया जाए, लोगों का विश्वास और स्वीकार्यता अर्जित कर सकेगी। जैसे-जैसे तनाव हल्का होगा और समेकन बहाल होता जाएगा, समग्र मांग में जीएफसीई के कम योगदान की उम्मीद करना समझदारी होगी। राजकोषीय राजस्व को बढ़ावा देने एवं इस संक्रमणकाल की तकलीफों को कम करने के लिए कर के चूककर्ताओं (टैक्स डिफॉल्टर्स) का पता लगाने व पहचान करने में तथा आय व संपदा पैरामीटर्स को ट्रैक करते हुए एवं आटोमैटिक इनवाइस-मैचिंग, इंटेलिजेंस, प्रवर्तन, निरीक्षण और लेखापरीक्षा सहित विवरणियों व प्रक्रियाओं को आसान व युक्तिसंगत बनाकर इस (जीएसटी) व्यवस्था की चुनौतियों को दूर करते हुए करदाता आधार को बढ़ाने में बिग डाटा और प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जा सकता है। यह उचित होगा

कि एक स्वतंत्र समिति द्वारा जीएसटी के अनुभवों के मूल्यांकन पर विचार किया जाए जो उससे अब तक प्राप्त सबक के आधार पर आगे की दिशा बता सके। उद्योगों को दिए जाने वाले राजकोषीय प्रोत्साहनों की दिशा बदलकर उत्पादन देने वाली श्रम-प्रधान कंपनियों की ओर किया जा सकता है ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो सकें।

1.32 निवेश मांग के संकेतक-पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन जून 2020 में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन 36.9 प्रतिशत संकुचित हुआ है (अप्रैल-जून 2020 के दौरान -64.4 प्रतिशत) और जुलाई 2020 में पूंजीगत वस्तुओं का आयात 24.7 प्रतिशत घट गया (अप्रैल-जून 2020 के दौरान -46.7 प्रतिशत)। निर्माण क्षेत्र में तीव्र गिरावट का रुख दिखाई दिया, जैसा कि जुलाई 2020 में इस्पात की खपत से पता चलता है (-29.1 प्रतिशत और अप्रैल-जून 2020 के दौरान -57.9 प्रतिशत) और सीमेंट का उत्पादन जो जून 2020 में 6.9 प्रतिशत संकुचित हुआ (अप्रैल-जून 2020 के दौरान -38.8 प्रतिशत)। क्षमता उपयोग के घटते स्तर, उपभोक्ता मांग के कमजोर होते जाने तथा दबावग्रस्त तुलनपत्रों के अंबार (ओवरहैंग) से नये निवेश में बाधा आ रही है। सितंबर 2019 में की गई कर कटौती का इस्तेमाल ऋण चुकाने, नकदीशेष की वृद्धि तथा अन्य चालू आस्तियों के लिए किया गया बजाय इसके कि पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के चक्र को दुबारा शुरू किया जाता। ये संबंधित घटनाक्रम बताते हैं कि निवेश की ललक में दम नहीं है तथा इसे और सुधारों की जरूरत है।

1.33 केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र विनियामक के अधीन प्रमुख बंदरगाहों (पोर्ट) का निजीकरण और इस्पात, कोयला, बिजली, भूमि, रेलवे की आस्तियों के मौद्रिकरण द्वारा फंड किया गया लक्ष्यित सार्वजनिक निवेश ही निजी निवेश के समुत्थान और निजी निवेश को आकर्षित करने का रास्ता हो सकता है। वस्तुतः, संरचनागत सुधार के लिए भूमि, श्रम, तथा पावर के संबंध में माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद जैसा एक शीर्ष प्राधिकार स्थापित किया जा सकता है। इनमें त्वरित कार्यान्वयन के साथ राष्ट्रीय अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) पाइपलाइन, उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम सड़क गलियारा (रोड

कॉरीडोर) और एक उच्च गति वाली रेल परियोजना आ सकती है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज की सफलताओं पर आधारित हो तथा साथ ही, व्यापार भावना और निवेश के लिए पर्यावरण में सुधार के कदम शामिल हों। राज्यों को अपने क्षेत्राधिकार में मुकदमेबाजी से मुक्त आधुनिक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता से युक्त भूमि का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। बिजली क्षेत्र में, सौर पैनलों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके और दूरदराज के क्षेत्रों को परिक्षिप्त (डिस्पर्सड) ट्रांसमिशन लिंक से जोड़कर अक्षय ऊर्जा में भारत को विश्व में अग्रणी बनने की छलांग का अवसर मिला है। समग्र रूप से क्षेत्र के लिए, टैरिफ संरचना के माध्यम से क्रॉस-सब्सिडी का उन्मूलन एक प्राथमिकता होनी चाहिए, एवं सब्सिडी का यदि कोई प्रावधान हो तो, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और साथ ही बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स)के निजीकरण पर भी ध्यान देना चाहिए। रेलवे के संबंध में, विनिर्माण इकाइयों को कॉरपोरेटाइज करने के पक्ष में मजबूत आधार हैं। भूमि बैंकों की विकास क्षमता का फायदा उठाया जा सकता है, विशेष रूप से महानगरीय क्षेत्रों में, वाणिज्यिक अचल संपत्ति के विकास के लिए निजी क्षेत्र को दीर्घकालिक पट्टे पर देकर। बुनियादी ढांचे-भूमि; खरीद नियम; परियोजना जोखिम-साझाकरण तंत्रों की उपलब्धता में बाधाओं को दूर करके रेलवे में एफडीआई को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कच्चे तेल के लिए की गई पहल सहित रणनीतिक सामग्रियों के पर्याप्त भंडार के निर्माण के संबंध में एक व्यापक नीति की आवश्यकता है।

1.34 वित्तपोषण के विकल्पों (फाइनेंसिंग ऑप्शन्स) के विविधीकरण की स्पष्ट आवश्यकता है। बैंक वित्त का विकल्प अध्यवसाय से तैयार किया जाना चाहिए – पूंजी बाजार तथा एफडीआई अपेक्षाकृत दीर्घावधि दृष्टिकोण वाले निवेशकों को लाने के अवसर प्रदान करते हैं जो टिकाऊ पूंजी एवं अंतर्निहित प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने में सहायक होती है। वर्ष 2015 में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत कार्रवाई थी। कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को बढ़ावा देना, दबावग्रस्त आस्तियों की समस्या के लिए बाजार-आधारित समाधान को प्रोत्साहित करने

के लिए प्रतिभूतिकरण, और उचित मूल्य-निर्धारण एवं उपयोक्ता-प्रभार (यूजर चार्ज) की वसूली के मुद्दों की नीति में प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। साथ ही अवसंरचना वित्त (इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस) कंपनियों के रूप में वर्गीकृत विशिष्ट एनबीएफसी की उपस्थिति बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

1.35 पिछले पांच वर्षों में देश में सड़क, नागरिक विमानन तथा हवाई अड्डा संपर्क (कनेक्टिविटी), दूरसंचार (इंटरनेट और ब्राडबैंड पैठ (पेनेट्रेशन) सहित) तथा बंदरगाहों(पोर्ट्स) के क्षेत्र में आधुनिक भौतिक अवसंरचना के निर्माण में हुई प्रगति उल्लेखनीय रही है। भारत ने शहरों में सामूहिक यातायात (अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन) के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं में भी प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। फिर भी, अवसंरचना का अंतराल अभी भी काफी बड़ा है और आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, वर्ष 2040 तक इसमें लगभग 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश की आवश्यकता है जिसमें अवसंरचना की खराब गुणवत्ता को उन्नत (अपग्रेड) करने पर जोर दिया जाना होगा। वैश्विक स्पर्धा सूचकांक और व्यवस्था (लाजिस्टिक्स) निष्पादन में अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की गुणवत्ता के लिए भारत 140 देशों में 70वें स्थान पर है। विश्व बैंक के लाजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक (एलपीआई) में भी भारत का स्थान 160 देशों में काफी नीचे 44वें स्थान पर है। बैंकों द्वारा अवसंरचना के लिए उधार देने से जुड़ी अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का स्तर भी ऊँचाई पर रहा है। कोविड-19 के संदर्भ में, कुछ लक्षित विशाल अवसंरचना परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में बड़ा प्रयास अर्थव्यवस्था में दुबारा जान डाल सकता है।

1.36 यही वह समय है जब कारोबारी वातावरण को बेहतर बनाते हुए उद्यमीय ऊर्जाओं के दरवाजे खोलने तथा जोखिम की लालसा को बढ़ाने की ज़रूरत है। संविदाओं को तेजी से लागू करना, साथ ही न्यायिक एवं इन्सालवेंसी क्षमताओं को बढ़ाया जाना खेल का पासा पलटने जैसा साबित होगा। संपत्तियों के पंजीकरण को वर्तमान 58 दिन से तेज किया जा सकता है, तथा एक केंद्रीकृत वेबसाइट सभी प्रकार के विनियामकीय अनुपालन की अपेक्षाओं के बारे में वास्तविक समय में सूचनाएं प्रदान कर सकती है। सामान्य रूप से कहा जाए तो अनुपालन संबंधी बोझ

को काफी हद तक व्यवस्थित बनाया जा सकता है। कोविड-19 के संकट का इस्तेमाल एक अवसर के रूप में किया जा सकता है तथा शिक्षा व प्रशिक्षण की आनलाइन व्यवस्था का इस्तेमाल करते हुए कौशल विकास करके एवं पुनः कौशल प्रदान करके सामाजिक अवसंरचना में सुधार की प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है ताकि एक ऐसा श्रमिक बल उन कौशलों से लैस रहे जो अवसंरचना पर ज़बरदस्त ज़ोर दिए जाने की गति को कायम रख सके।

1.37 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पिछले दो दशकों से अधिक समय से भारत की आर्थिक प्रगति का एक इंजन रहा है। लेनदेन व संचार की लागतों में कमी और पूंजी की गुणवत्ता में वृद्धि द्वारा आईसीटी का दोहन भविष्य की विकासात्मक रणनीतियों का प्रमुख तत्व होना चाहिए। इससे उत्पादकता का लाभ चारों तरफ मिल सकता है, जिसमें भारत तथा विदेशों में सक्षम, भरोसेमंद और ज्ञान-आधारित साल्यूशंस की कम लागत पर आपूर्ति हो सकेगी। भारतीय आईटी फर्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), रोबोटिक्स तथा ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एप्लीकेशंस का विकास करने में सबसे आगे हैं। इस खास विशिष्टता का भरपूर उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि एक नवोन्मेष हब के रूप में भारत की हैसियत सुदृढ़ बन सके, साथ ही भारत का 'स्टार्ट-अप भारत' अभियान आगे बढ़े जो देश के युवा उद्यमियों की क्षमताओं को पहचान प्रदान करता है तथा उन्हें एक सहायक परितंत्र (ईकोसिस्टम) उपलब्ध कराता है। हेल्थटेक और फिनटेक जहां अग्रणी क्षेत्र बन गए हैं, वहीं भारतीय उद्यमी अन्य सभी क्षेत्रों एवं बाजारों में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और इस परितंत्र को गहन तथा विस्तृत बना सकते हैं, खासतौर से लघु एवं मझोले कारोबार में तथा कम एवं मध्यम आय-समूहों को सेवाएं उपलब्ध करवाते हुए। कोविड-19 के पूर्व भी, डिजिटल प्रौद्योगिकी में तेज उन्नयन तथा आधुनिक कंप्यूटिंग/विश्लेषणात्मक क्षमताओं के साथ विश्व भर में एक प्रौद्योगिकीय मंथन चल रहा था। टैरिफ संबंधी बाधाएं तथा डाटा की निजता (प्राइवैसी) एवं डाटा की सुरक्षा के मुद्दे जहां चुनौती खड़ी कर सकते हैं, वहीं सृजनात्मक विध्वंस (डिस्ट्रक्शन) एक सुदृढ़ गतिमान अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। आईटी क्षेत्र इस

प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा इससे होने वाले परिणामों को संभालने में भी सक्षम है। नई फर्मों एवं स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देना तथा उन्हें बनाए रखना भारत में रोजगार-सृजन एवं उच्च उत्पादकता-जन्य आर्थिक विकास को कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिशा में संसाधनों का पुनर्विन्यास तथा नीति का फोकस आवश्यक होगा। गतिमान उद्यमिता, नवोन्मेष तथा स्टार्ट-अप्स में निहित विचारों को पोषण देकर यथार्थ रूप देने की क्षमता ही आईसीटी की सफलता की कसौटी है।

1.38 एक अर्थक्षम भुगतान संतुलन और सक्रिय विनिर्माण क्षेत्र की कुंजी निर्यात के हाथ है। महामारी ने वैश्विक मूल्य-शृंखला (वैल्यू चेन्स) के अंतरराष्ट्रीय परिवेश को बदल कर रख दिया है, और गतिशील निर्यात रणनीति में इसके निहितार्थ उत्पाद-गंतव्यों के चुनाव के लिए हैं। संसाधनों को कम-कम एवं दूर-दूर फैलाने के बजाय, इस समय उदीयमान निर्यात श्रेणियों का पता लगाने की ज़रूरत है जो उत्पादकता का लाभ कमा रही हैं तथा जिनके पास सक्रिय क्षैतिज व ऊर्ध्व कड़ियां (होरिजेंटल एंड वर्टिकल लिंकेजेज) हैं, जो उभरती वैश्विक मूल्य-शृंखला में अपनी उपस्थिति को मज़बूती प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में उत्पादन के आधार में सतत विविधीकरण नये अवसरों को प्रस्तुत करता है, बशर्ते अपनी विनिर्माण व्यवस्थाओं के लिए नए लोकेशंस खोज रही कंपनियों के लिए मौजूदा पसंदीदा स्थानों पर स्पर्धा के लिए भारत उच्च-स्तरीय वर्गों (हाई-एंड सेगमेंट) में एफडीआई पर लीवरेज करने में सक्षम हो। जेनेरिक तथा फार्मास्यूटिकल्स दवाइयों के निर्यात में विश्व का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता होने के नाते भारत हमेशा से अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में रहा है। भारत के लिए आवश्यक है कि वह वैश्विक मानकों के अनुसार किफायती तथा उच्च गुणवत्ता वाली विनिर्माण प्रक्रियाओं का विकास करके सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स घटकों (एपीआई) में अपने बाजार का हिस्सा पुनः प्राप्त करे। निर्यात के एक अन्य समूह - रेडीमेड कपड़े; कीमती पत्थर और आभूषण- में नयी स्पर्धा में भारत अपना स्थान क्रमशः खोता जा रहा है- परंपरागत रूप से यह समूह श्रमिक-प्रधान है; उसमें पुनः स्पर्धात्मकता को पा लेना ऐसे श्रम सुधार पर निर्भर है जो बड़े पैमाने की किफायतों (स्केल इकॉनॉमीज़) को बंधनमुक्त कर दे।

1.39 विदेश व्यापार नीति को निःशुल्क/वरीय व्यापार व्यवस्थाओं के माध्यम से निर्यात की लीवरेजिंग पर अधिकाधिक ध्यान देना चाहिए। इस संदर्भ में, भारत-ईयू मुक्त व्यापार करार तथा यूके के साथ ब्रेक्सिट के पश्चात मुक्त व्यापार करार /वरीयता व्यवस्था (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट/ प्रेफरेंशियल अरेंजमेंट) संपन्न होने पर पहले शुरुआत का फायदा मिल सकता है। भारत को भी चाहिए कि वह स्पर्धा की सीढ़ी पर आगे बढ़ रहे नये निर्यात उत्पादों के लिए ज़रूरी दुर्लभ सामग्री की आपूर्ति करने वाले देशों के साथ विशेष व्यापार व्यवस्था गठबंधन करे। आईसीटी, वित्त तथा कारोबारी सेवाओं जैसे क्षेत्र से उत्पादकता लाभ के दोहन के साथ-साथ पहले से ही चिह्नित क्षेत्र जैसे – आटो पार्ट्स, ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, खाद्यान्न प्रसंस्करण –की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुदृढ़ ढांचा तैयार करना निर्यात रणनीति की एक केंद्रीय विशेषता होनी चाहिए। इस रणनीति में समय व लागत में कमी द्वारा व्यापार परितंत्र में परिवर्तन के उद्देश्य वाली राष्ट्रीय व्यापार सुगमता योजना (नेशनल ट्रेड फेशिलिटेशन स्कीम), के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अत्यधिक कुशल संधारतंत्र (लॉजिस्टिक्स) की भी आवश्यकता होगी। भारत के बहुत से पारंपरिक निर्यातों विशेषतः कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के उत्पादों के लिए कृषि क्षेत्र की आय को दुगुना करने के लक्ष्य से बेहतर तालमेल के साथ-साथ व्यापार नीति में स्थिरता महत्वपूर्ण है। विनिर्माण के निर्यात के संदर्भ में, विनिर्माण उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापनाके लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की तरह क्लस्टर-आधारित विनिर्माता निर्यात लॉन्चिंग पैड्स पर नए सिरे से जोर देना उचित रहेगा जो निर्यात और एफडीआई के बीच स्वाभाविक लिंक पर लीवरेज करेगा।

1.40 उत्पादन गतिविधियों की ओर रुख करें तो यह पाते हैं कि प्रतिकूलताओं के बावजूद भारतीय कृषि क्षेत्र एक स्पष्ट बदलाव के दौर से गुजर रहा है। खाद्यान्न का कुल उत्पादन 2019-20 में 2966.5 लाख टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंचा, जबकि कुल बागबानी उत्पादन – जिसका फार्म क्षेत्र के जीवीए में हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत है –भी अब तक सबसे ऊंचे स्तर 3204.8 लाख टन तक पहुंचा। भारत का शुमार अब विश्व में दूध,

अनाज, दालें, सब्जियां, फल, कपास, गन्ना, मत्स्य तथा कुक्कुट एवं मवेशियों के अग्रणी उत्पादकों में होता है। परिदृश्य के धुंधलके में भी ये उपलब्धियां विशेष उल्लेखनीय हैं। इससे ही ऐतिहासिक राष्ट्र खद्यान्न सुरक्षा अधिनियम(एनएफएसए) पारित करने का विश्वास प्राप्त हुआ है जो खद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रमों को दो-तिहाई आबादी के लिए सब्सिडी-प्राप्त खद्यान्न को कानूनी अधिकार में परिवर्तित करता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नामक विश्व की सबसे बड़ी खद्यान्न सुरक्षा योजना की घोषणा की। जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं – विशेषतः प्रवासी मजदूरों, फँसे पड़े और जरूरतमंद परिवारों के लिए - आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के अंतर्गत 8 लाख टन के खद्यान्न का प्रावधान किया गया है।

1.41 इसके आगे, कृषि क्षेत्र के पक्ष में व्यापार की शर्तों को बदलना इस गतिशील बदलाव को बनाए रखने तथा कृषि उत्पादन में सकारात्मक आपूर्ति संबंधी रेस्पांस की कुंजी है। अनुभव यह बताते हैं कि उन अवधियों में जब व्यापार की शर्तें कृषि के अनुकूल रहीं, तब कृषि क्षेत्र के सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) में 3 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक औसत वृद्धि होती थी। अब तक, प्रोत्साहन का मुख्य जरिया न्यूनतम समर्थन मूल्य था, लेकिन अनुभव यह रहा है कि कीमत वाले प्रोत्साहन महंगे, अकुशल एवं स्वरूप को बिगाड़ने वाले भी रहे हैं। भारत अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां अधिशेष का प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। प्राथमिकता इस बात की है कि नीतिगत रणनितियों का रुख उस दिशा में हो जो उपभोक्ता के लिए उचित खद्यान्न मूल्य के साथ-साथ कृषकों की आय में सतत वृद्धि सुनिश्चित कर सके। इस स्तर पर एक कुशल घरेलू आपूर्ति श्रृंखला का होना बहुत ज़रूरी है। तदनुसार, अब उन प्रमुख सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो कृषि में निःशुल्क व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए किए जा रहे हैं। पहला, आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) में संशोधन का उद्देश्य है वेयरहाउस, प्रशीतनगृह, तथा बाजार-स्थलें के साथ-साथ आपूर्ति-श्रृंखला

अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना है। दूसरा, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुगमन) अध्यादेश 2020 का लक्ष्य यह है कि कृषि उत्पाद में बाधा-रहित व्यापार को सुविधाजनक बनाया जाए। तीसरा, फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस एस्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज़ ऑर्डिनेंस, 2020, कृषकों को प्रोसेसर, एग्रीगेटर्स, थोकविक्रेता, बड़े फुटकर विक्रेता तथा निर्यातकों से प्रभावी एवं पारदर्शी तरीके से व्यवहार करने का अधिकार देगा। सशक्त बनाने वाले इस कानूनी ढांचे के साथ ध्यान इन बातों पर केंद्रित किया जाना चाहिए: (ए) फसलों का विविधीकरण, पानीखोरों/अधिक पानी पीने वाली फसलों (वाटर गजलर्स) पर जोर कम, भले ही राजनैतिक दृष्टि से यह कितना ही मुश्किल क्यों न हो; (बी) खाद्यान्न प्रसंस्करण जो कृषि उत्पाद की निधानी आयु (शेल्फ लाइफ़) को बढ़ाए तथा फसल कटने के बाद बरबादी को न्यूनतम बनाना; (सी) कृषिगत निर्यात जो भारतीय किसानों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शर्तों एवं प्रौद्योगिकी से परिचित कराता है तथा (डी) कृषि क्षेत्र में सरकारी और निजी पूंजी निर्माण।

1.42 भारतीय विनिर्माण क्षेत्र एक अर्से से संरचनागत शिथिलता की चपेट में आ गया है। इस गिरावट की स्थिति को उलटने के लिए पूर्णतः नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। टैरिफ और गैर-टैरिफ प्रतिबंधों का प्रभाव घरेलू विनिर्माण क्षेत्र का वैश्विक अर्थव्यवस्था से विच्छेद का रहा है। उन्हें आसान बनाने से नये निवेश आएंगे तथा बेहतर कारोबार करने के वातावरण में दक्षता का भी फायदा मिलेगा। भौतिक अवसंरचना की गुणवत्ता और दक्षता जो अभी भी विश्वस्तरीय औसत से काफी पीछे है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि विनिर्माण को उड़ान भरने में सहायता मिल सके। विश्व की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं व प्रणाली के साथ बेंचमार्किंग और दिवाला और अक्षमता प्रक्रियाओं को दक्ष बनाते हुए कारपोरेट्स के दबावग्रस्त तुलनपत्र को साफ-सुथरा बनाकर इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। बड़ी भारतीय फर्मों को चाहिए कि वे अपनी वित्तपोषण की आवश्यकताओं का विविधीकरण करें और खासतौर से

अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए बैंक-आधारित प्रणाली पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को कम करें। भारत के अनुकूल बनाए गए सरकारी-निजी सहभागिता के व्यवहार्य मॉडल की जरूरत पर जितना कहा जाए कम है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विरासती समस्याओं यथा, भूमि अधिग्रहण तथा क्षतिपूर्ति का भुगतान, पर्यावरणीय मंजूरी, परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के कारण अधिक समय एवं लागत लगने जैसी स्थितियों का तुरंत समाधान करने की आवश्यकता है। श्रमिक विनियमन में सुधार तथा सकारात्मक कार्रवाई द्वारा कार्यबल में अधिक संख्या में महिलाओं की सहभागिता से उत्पादन की लागत कम होगी तथा उत्पादकता बढ़ेगी।

1.43 एमएसएमई क्षेत्र में विकास का इंजन होने की संभावना है, किंतु विभिन्न संरचनागत कारणों से लंबे समय से इस क्षेत्र का प्रदर्शन अपनी क्षमता से कम रहा है। यह क्षेत्र पर्याप्त सूचनाओं के अभाव में क्रेडिट की उच्च लागत, आधुनिक प्रौद्योगिकी के अभाव, अनुसंधान एवं नवोन्मेष के बिना, अपर्याप्त प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा जटिल श्रमिक कानून के कारण बाधित रहा है। एमएसएमई में प्रमुख सुधार अर्थात् विनिर्माण एवं सेवा-आधारित एमएसएमई के बीच परिभाषागत अंतर को दूर करने, एमएसएमई के रूप में किसी उद्यम को परिभाषित करने के लिए निर्धारित सीमा (श्रेषहोल्ड लिमिट) को बढ़ाने, तथा एमएसएमई को परिभाषित करने के लिए निवेश के मानदंड के साथ टर्नओवर को भी एक मानदंड के रूप में जोड़े जाने से दूरगामी परिणामों की शुरुआत हो सकती हैं जो भारत में विनिर्माण की शक्ल बदल सकता है।

1.44 पिछले दो दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित हुई है, जिसमें बैंकिंग और वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, परिवहन, दूरसंचार, ई-कामर्स सहित व्यापार एवं अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र में विभिन्न स्तर के कौशल एवं संगठनात्मक अपेक्षाओं वाली आर्थिक गतिविधियों के विविध समूह शामिल हैं। तथापि, वर्ष 2014-15 में उंचाई पर पहुंचने के बाद सेवा क्षेत्र में लगातार नरमी आई है। उत्पादन को बल प्रदान

करने वाले उत्पादकता लाभ के सृजन के अलावा, भारत में सेवा क्षेत्र का महत्व रोजगार पैदा करने की दृष्टि से भी है क्योंकि मापित रोजगार में 44.4 प्रतिशत<sup>2</sup> हिस्से के साथ यह क्षेत्र सबसे बड़ा नियोज्य है।

1.45 पिछले तीन दशकों में सूचना और दूरसंचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में प्राप्त की गई सफलता को अन्य क्षेत्रों तक विशेषतः स्वास्थ्य सुरक्षा तथा पर्यटन क्षेत्र में भी ले जाने की आवश्यकता है जहाँ भारत स्वाभाविक रूप से बेहतर स्थिति में है। ऐसी प्रतिभाओं को भी पोषित करने की आवश्यकता है जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आईओटी) तथा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उभरते हुए अवसरों का दोहन कर सकें। संसाधनों तथा नीति का फोकस इस दिशा में मोड़ना आवश्यक होगा तथा इस क्षेत्र के लिए प्रमुख चुनौती होगी, नवोन्मेष तथा विचारों को सींचकर वास्तविक धरातल पर साकार करने की क्षमता। इस संदर्भ में निजी उद्यम एवं निवेश की भूमिका अहम होगी।

1.46 2016 में अपनाए गए मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लचीले ढांचे के अंतर्गत 2019-20 तक हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति औसतन 3.9 प्रतिशत तक रही थी, जो 4 प्रतिशत के लक्ष्य के काफी नजदीक है। इसने मौद्रिक नीति के संचालन को विश्वसनीयता दी है, निवेशकों में विश्वास भरा है तथा मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को स्थिर रखा है। परिणामतः मौद्रिक नीति की दिशा को निरंतर आठ तिमाहियों से पीछे होती जा रही संवृद्धि को अवलंब देने की ओर मोड़ा भी जा सका। तदनुसार, फरवरी 2019 से नीतिगत दर को कुल 250 आधार अंकों तक घटाया गया, जिसमें जीडीपी के लगभग 5.0 प्रतिशत तक की चलनिधि के समावेश का सहयोग रहा। नीतिगत दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर है। इस समन्वित रणनीति ने वित्तीय बाजार और वित्तीय संस्थाओं को सामान्य रूप से कार्यशील बनाए रखा है, कोविड-19 के प्रकोप के कारण चलनिधि संबंधी दबाव को दूर किया है, वित्तीय स्थितियों को काफी हद तक सहज बनाकर गृहस्थों (हाउसहोल्ड्स) एवं कारोबारों को विश्वास प्रदान किया तथा वित्त की जीवनशक्ति को प्रवाहित रखा।

1.47 एमपीसी ने अगस्त 2020 की अपनी शुरुआती बैठक में आपूर्ति-श्रृंखला के अवरोधों तथा बढ़ती लागतों के दबाव के कारण समष्टि-आर्थिक परिदृश्य में व्याप्त अत्यधिक अनिश्चितता पर ध्यान दिया। समिति की प्रत्याशा थी कि 2020-21 की दूसरी तिमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति ऊँचाई पर बनी रहेगी, किंतु अनुकूल आधारगत प्रभाव के कारण 2020-21 की दूसरी छमाही में इसके नरम पड़ने की संभावना है। जहां तक संवृद्धि की संभावनाओं का संबंध है, एमपीसी ने प्रत्याशा की कि वर्ष 2020-21 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि कुल मिलाकर ऋणात्मक रहेगी। एमपीसी का विचार था कि कोविड-19 महामारी पर शीघ्र नियंत्रण हो जाने से परिदृश्य बेहतर बन सकता है। महामारी का अधिक समय तक खिंचना, पूर्वानुमान से कम मानसून रहना तथा विश्व में वित्तीय बाजार की अस्थिरता प्रमुख अधोमुखी जोखिम हैं। ऐसे परिवेश में, एमपीसी का विचार है कि मौद्रिक नीति के संचालन में अर्थव्यवस्था के समुत्थान को सहयोग प्रमुख हो जाता है। आगे मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाई के लिए जहां और गुंजाइश मौजूद है, वहीं यह महत्वपूर्ण है कि इसका उपयोग विवकपूर्ण ढंग से किया जाए ताकि अंतर्निहित आर्थिक गतिविधियों के लाभकारी प्रभाव अधिकाधिक हों।

1.48 साथ ही, एमपीसी इसके मध्यावधि मुद्रास्फीति के लक्ष्य के उर्ध्वमुखी जोखिम प्रति सचेत भी थी। हेडलाइन मुद्रास्फीति के लक्ष्य के आसपास सख्त सीमा के ऊपरी दायरे से अधिक बने होने, लेकिन साथ ही आर्थिक गतिविधियों एवं संभावनाओं को कमजोर और अनिश्चित देखते हुए एमपीसी ने यह नोट किया कि 250 आधार अंक की संचयी कटौती अर्थव्यवस्था में अपना काम कर रही है, तथा मुद्रा, बांड व क्रेडिट बाजारों में ब्याज दरों को न्यून बना रही है, और स्प्रेड को संकरा कर रही है। तदनुसार, मुद्रास्फीति में टिकाऊ स्वरूप की कमी की प्रतीक्षा करते हुए एमपीसी ने विराम का निर्णय लिया ताकि अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान को सहारा देने के लिए उपलब्ध गुंजाइश का उपयोग किया जा सके।

1.49 वित्तीय क्षेत्र की ओर देखें तो, भारतीय बैंकिंग को जोखिम विमुखता से छुटकारा दिलाना होगा जो अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र की ओर क्रेडिट का प्रवाह रोक रही है तथा

अर्थव्यवस्था में प्रमुख वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंकों की भूमिका को क्षति पहुँचा रही है। समष्टि-आर्थिक एवं वित्तीय परिवेश में आई गिरावट बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता तथा लाभप्रदता को क्षति पहुँचा रही है। महामारी के कारण आवश्यक हुई विनियामकीय रियायतों- ऋण की किस्तों में स्थगन, ब्याज भुगतान का आस्थगन तथा उसकी पुनर्चना-की बारीक निगरानी और विवेकपूर्ण उपयोग न हो तो बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य पर भी इनका प्रभाव संभावित है। हालांकि मार्च, 2020 में, घटते गिरावट अनुपात (स्लिपेज रेशियो) के साथ सकल एवं निवल अनर्जक आस्ति अनुपातों में भी कमी आ गई थी, फिर भी महामारी का आर्थिक परिणाम इस समुत्थानशीलता की परीक्षा ले सकता है, विशेषतः इसलिए कि, महामारी को देखते हुए घोषित विनियामकीय रियायतों ने इस प्रकोपजन्य दबाव पर मुखौटा डाल दिया है। जुलाई 2020 में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मैक्रो दबाव परीक्षण से ज्ञात होता है कि बेसलाइन परिदृश्य के अंतर्गत अनर्जक आस्तियां अपने मार्च, 2020 के स्तर से 1.5 गुना और अत्यधिक दबाव के परिदृश्य में 1.7 गुना बढ़ सकती हैं। बेसलाइन परिदृश्य के अंतर्गत प्रणाली स्तर पर सीआरएआर मार्च, 2020 के स्तर से मार्च 2021 में 13.3 प्रतिशत तक तथा अत्यधिक दबाव के परिदृश्य में 11.8 प्रतिशत तक घट सकता है।

1.50 इस परिदृश्य में सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए पुनः पूंजीकरण की योजना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं, जो कि ऐतिहासिक हानि की घटनाओं के आधार पर नपे-तुले ढंग से तय (कैलिब्रेट) की जाती हैं, संभव है महामारी के बाद के नुकसान को पूरी तरह संभालने के लिए पर्याप्त न रह जाएं। रिजर्व बैंक ने बैंकों व एनबीएफसी को पहले ही कोविड-19 दबाव परीक्षण (स्ट्रेस टेस्ट) करने और अग्रसक्रियता से उपचारात्मक कार्रवाई करने को कह दिया है। अतीत की तुलना में अधिक बार, विविध और बड़े जोखिम वाली घटनाओं के पूर्वानुमान में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पूंजी जुटाने के साथ-साथ

समुत्थानशीलता निर्मित करने की क्षमता बैंकों में अभिशासन मानकों पर निर्भर होगी। इस संबंध में, रिजर्व बैंक ने "भारत में वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन" ("गवर्नेंस इन कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया") पर एक चर्चा पत्र जारी किया है, जिसका उद्देश्य घरेलू वित्तीय प्रणाली के संदर्भ के प्रति सचेत रहते हुए नियामक ढांचे को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप ढालना है। चर्चा पत्र का मुख्य जोर निदेशक मंडल को सशक्त बनाना है। बोर्ड, अपनी ओर से, संगठन की संस्कृति और मूल्य स्थापित करे; हितों के टकराव को पहचाने और उन्हें संभाले; जोखिम की लालसा तैयार करे और इस लालसा में निहित जोखिमों का प्रबंधन करे; वरिष्ठ प्रबंधन पर निगरानी रखे; और विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से निगरानी और आश्वासन कार्यों को सशक्त बनाए। उभरते नियमों के साथ तालमेल बिठाते हुए, रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को दोतरफा होना होगा - पहला, विनियमित संस्थाओं के आंतरिक बचाव पक्ष को मजबूत करना; और दूसरा, पूर्व चेतावनी संकेतों की पहचान करने और सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। व्यावसायिक मॉडल, अभिशासन और आश्वासन कार्यों (अनुपालन, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षा और सतर्कता कार्यों) के मूल्यांकन पर अधिक जोर देने की आवश्यकता होगी। यह दोहराना महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 नियंत्रण के बाद की अवधि में, तत्संबंधी नियामक उपायों को क्रमिक रूप से वापस लिए जाने के मार्ग पर बहुत ही सावधानी से चला जाए और विनियामक छूटों पर आश्रित हुए बिना वित्तीय क्षेत्र सामान्य कामकाज पर वापस लौटे।

1.51 एनबीएफसी क्षेत्र की ओर रुख करें तो, डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ अभिनव तरीकों से वित्तीय सेवाएं देने के लिए गैर-पारंपरिक और डिजिटल खिलाड़ी इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। रिजर्व बैंक का लक्ष्य इस क्षेत्र को मजबूत करना, स्थिरता बनाए रखना और विनियामक मध्यस्थता की गुंजाइश कम करना है। विनियमन और पर्यवेक्षण का एक इष्टतम स्तर प्राप्त करना है ताकि एनबीएफसी क्षेत्र वित्तीय रूप से लचीला और मजबूत हो जो विभिन्न प्रकार के ग्राहकों व विशिष्ट क्षेत्रों



की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा बैंकों को पूरकता और प्रतिस्पर्धा प्रदान करे। एनबीएफसी क्षेत्र काफी हद तक बाजार और बैंक उधार पर निर्भर करता है, जिससे बैंकों और वित्तीय बाजारों के साथ परस्पर-संपर्कों का एक संजाल तैयार होता है। चूँकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (एचएफसी) अब रिजर्व बैंक के विनियामक दायरे में आती हैं, एनबीएफसी के लिए लागू होने वाले नियमों का एचएफसी के लिए नियमों के साथ सामंजस्य बैठाने की प्रक्रिया प्राथमिक हो जाती है। एनबीएफसी के लिए एक मजबूत चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचा मौजूद है जो कुछ समय में एचएफसी पर भी लागू होगा ताकि स्पष्टतः निर्दिष्ट भूमिका व जिम्मेदारियों वाले कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) सहित उचित अभिशासन और जोखिम प्रबंधन संरचनाओं को सुनिश्चित किया जा सके। एनबीएफसी/एचएफसी के प्रणालीगत महत्व और वित्तीय प्रणाली के साथ उनके परस्पर-संपर्कों की उचित मान्यता और उचित रूप से एक्सपोजर सीमा को नियंत्रित करके उच्च ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना, सह-वित्तपोषण और एनबीएफसी को ऋण देने के लिए वाणिज्यिक बैंक को सक्षम बनाना और हितधारकों के साथ सक्रिय जुड़ाव को बढ़ावा देना इस क्षेत्र में हो रही कार्रवाइयों की प्रमुख बातें हैं।

1.52 कोविड-19 के मद्देनजर, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता डिजिटल भुगतान की व्यापक स्वीकृति को गति प्रदान कर रहे हैं। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) के परिचालन से स्वीकृति के बुनियादी ढांचे को देश भर में, विशेषतः अल्पसेवित क्षेत्रों में, लगाए जाने की प्रक्रिया को बल मिलने और भुगतान लेनदेन के डिजिटलीकरण में सहायता की उम्मीद है। रिजर्व बैंक पूरे देश में डिजिटल भुगतान को और गहन करने के लिए ऑफलाइन भुगतान समाधानों के विकास को बढ़ावा देगा। खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए नए अखिल भारतीय छत्र इकाइयों (अम्ब्रेला एंटीटीज) को प्राधिकृत करने हेतु हाल में जारी रूपरेखा, भुगतान परिदृश्य में नवोन्मेष और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी

और खुदरा भुगतान प्रणालियों में संकेंद्रण जोखिम को कम किया जा सकेगा। विनियामक और पर्यवेक्षी प्रक्रिया में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्व-विनियामक संगठन (नों) की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। अन्य कदमों में, अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को विफल लेनदेन के लिए ऑनलाइन भुगतान विवाद समाधान (ओडीआर) लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है।

1.53 देश में भुगतान परिदृश्य को बदलने के लिए कई प्रयास चल रहे हैं। केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली, अर्थात्, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली ग्राहक लेनदेन के लिए सुबह 7 से शाम 6 बजे तक उपलब्ध है; और दिसंबर 2019 से, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) प्रणाली चौबीसों घंटे - 24x7x365 काम कर रही है। एक अन्य उद्देश्य डिजिटल लेनदेन की लागत को कम करना भी है। तदनुसार, सदस्य बैंकों पर लागू एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए प्रसंस्करण शुल्क माफ कर दिए गए हैं और बदले में, उन्हें, इसका लाभ अपने ग्राहकों तक पहुँचाने की सलाह दी गई है। भावी मार्ग में, नवोन्मेषी विचारों के अंकुरण के उद्देश्य से वित्तीय क्षेत्र के लिए नवोन्मेष-केंद्र (इनोवेशन-हब) स्थापित करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और भुगतान प्रणालियों के विकास हेतु नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) जैसे छत्र संगठन/नों की लाइसेंसिंग शामिल होगी।

1.54 रिजर्व बैंक के मूल उद्देश्य, मिशन और दृष्टि की मध्यावधि रणनीति- 'उत्कर्ष 2022' - के अंतर्गत आने वाले वर्ष के लिए विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अपनाए गए प्रमुख प्रदियों (डिलिवरेबल्स) का कैनवास विस्तृत है। रणनीति के निष्पादन की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा। विनियमन और पर्यवेक्षण के क्षेत्र में, आवश्यक कौशल और विशेषज्ञता वाले एक विशेषज्ञ संवर्ग को विकसित किया जाएगा, और मौजूदा डेटाबेसों को जोड़कर इसे एक व्यापक पर्यवेक्षी डेटाबेस द्वारा समर्थित किया जाएगा। बेसल III मानकों के अनुरूप प्रतिभूतिकरण और परिचालन जोखिम पर

दिशानिर्देश निर्धारित किए जाएंगे। समाज के विशिष्ट वर्गों को लक्षित करने वाले ऑनलाइन वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल विकसित करके वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाया जाएगा। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वित्तीय शिक्षा संरचना से तथा तीन वर्तमान लोकपाल योजनाओं (ओम्बड्समैन स्कीम्स)<sup>3</sup> के एकीकरण हेतु आंतरिक समिति के परामर्शों के कार्यान्वयन से ग्राहक सुरक्षा को बल मिलेगा। वित्तीय बाजार के विकास में एक ऋण व्युत्पन्न बाजार का विकास, राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स) की शुरुआत और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए फेमा विनियमों का युक्तिकरण करना शामिल होगा। इन कदमों को संरचनागत वित्तीय संदेश प्रेषण समाधान (एसएफएमएस) के उन्नयन, स्वीकृति आधार-संरचना (एक्सेपटेंस प्लेटफॉर्म) की पैठ में सुधार और छोटे केंद्रों में बिक्री के बिंदु (पीओएस) की सुविधा जैसे तकनीकी विकासों से लैस किया जाएगा। इन प्रयासों के लिए रिजर्व बैंक के कर्मियों में कौशल विकसित करने हेतु प्रशिक्षण नीतियों में आपूर्ति (प्रशिक्षण के लिए प्रस्तुत पाठ्यक्रम), वितरण (कौन-कौन से पाठ्यक्रम, कौन, कहां और कैसे प्रदान करते हैं) और मूल्यांकन (संस्थानों, प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं के) शामिल होंगे। भौतिक बुनियादी ढाँचे के विकास के संदर्भ में, कम से कम एक मौजूदा कार्यालय और पांच मौजूदा आवासीय भवनों के लिए भारतीय हरित भवन परिषद (आईजीबीसी) / एकीकृत आवास आकलन हेतु हरित रेटिंग (जीआरआईएचए) से अपेक्षित रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य होगा।

1.55 भविष्य की इन रणनीतियों के लिए भी रिजर्व बैंक को सुप्रचलानिक रूप से (लाजिस्टिकली) सशक्त होने की आवश्यकता होगी। रिजर्व बैंक अपने डेटा वेयरहाउस सिस्टम को नए केंद्रीय अत्याधुनिक सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) में बदलने की प्रक्रिया में है, जो रिजर्व बैंक के

अधिकांश कार्य क्षेत्रों में डेटा की प्राप्ति, प्रसार और एनालिटिक्स को कवर करता है। नई तकनीकों को सुरक्षित तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग परीक्षण परिवेश (सैंडबॉक्स) स्थापित किया गया है। इसका उपयोग सीआईएमएसके साथ बैंकों की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) सर्वरों के सिस्टम-टू-सिस्टम एकीकरण के परीक्षण के लिए किया जाएगा। बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) को, जो बैंकिंग नेटवर्क और वित्तीय समावेश नीतियों को सपोर्ट करती है, सहकारी बैंकों, एटीएम और नियत स्थान (फिक्सड-लोकेशन) बिजनेस संवाददाताओं (बीसी) को शामिल करके विस्तारित किया जाएगा। नई सुविधाओं से युक्त एससीबीका सेंट्रल फ्रॉन्ट रजिस्ट्री (सीएफआर) पोर्टल, विकास के एक उन्नत चरण में है। रिजर्व बैंक का डेटा साइंस लैब (डीएसएल) नीति निर्माण और निगरानी हेतु इनपुट प्रदान करने के लिए डेटा की गुणवत्ता, पूर्वानुमान, चौकसी, पूर्व चेतावनी पहचान क्षमताओं में सुधार और बिग डेटा एनालिटिक्स के प्रयोग की दिशा में काम करेगा। डेटा वैज्ञानिकों, सांख्यिकीविदों, अर्थशास्त्रियों और आईटी कर्मियों के विशेषज्ञों की एक अंतर्विषयक (इंटरडिसिप्लिनरी) टीम पर आधारित डीएसएल का विस्तार किया जाएगा, जो रिजर्व बैंक के हित के विभिन्न क्षेत्रों में प्रोग्रामिंग, सांख्यिकीय विधियों, टेक्स्ट एंड डेटा माइनिंग और मशीन-लर्निंग से संबंधित विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करेंगे। सीआईएमएस परिवेश में एक ग्रैनुलर डेटा एक्सेस लैब (जीडीएएल) की योजना बनाई गई है जिसमें ग्रैनुलर डेटा की गोपनीयता की रक्षा के लिए डेटा-मास्किंग और अन्य एक्सेस प्रतिबंधों की तकनीकों की परिकल्पना है।

1.56 महामारी विश्व की अर्थव्यवस्था पर गहरी विकृतियां छोड़ जाएगी। भविष्य का आकार काफी हद तक कोविड-19 की उभरती तीव्रता, प्रसार और अवधि तथा उस मारीचिकेय (दुष्प्राप्य) टीके की खोज पर टिका हुआ है। कोविड -19 के

<sup>3</sup> इसमें बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006; एनबीएफसी लोकपाल योजना, 2018; और डिजिटल लेन-देन लोकपाल योजना, 2019 शामिल है।

बाद, यह सोच हावी है कि दुनिया फिर से वैसी नहीं होगी और इसकी एक नयी शकल उभर सकती है। महामारी काल के बाद, जब वित्तीय प्रोत्साहन (स्टिमुलस) और विनियामक सुलभता का असर इस समुत्थान से हटेगा तो दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह, भारत का संभावित उत्पादन एक संरचनात्मक गिरावट के दौर से गुजर सकता है। इसके अलावा, इस समुत्थान के अलग प्रकार की होने की संभावना है - जीएफसी की स्थिति समष्टि-आर्थिक स्थिरता के साथ वर्षों के मजबूत विकास के बाद पैदा हुई; इसके विपरीत, अर्थव्यवस्था को कोविड-19 की चोट, लगातार शिथिलता की मार के बाद, पड़ी है। इसके अलावा, जीएफसी मूल रूप से एक वित्तीय चरमराहट थी, जबकि यह महामारी एक स्वास्थ्य संकट है, जो पूरे वास्तविक और वित्तीय

क्षेत्रों में हानिकारक साबित हो सकती है। इस बेहिसाब मानवीय और आर्थिक क्षति के प्रभाव को कम करने के लिए, अब तक नीति प्राधिकारियों ने पारंपरिक और अपारंपरिक उपायों के साथ इस पर एक अभूतपूर्व बचाव वाली जवाबी कार्रवाई की है। महामारी के बाद वित्तीय प्रोत्साहन जब नपे-तुले और गैर-विघटनकारी तरीके से क्रमशः समेटा जाएगा, तब कारक (फैक्टर) और उत्पाद बाजारों, वित्तीय क्षेत्र, कानूनी ढांचे और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अत्यधिक गहन और व्यापक संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता होगी ताकि संभावित उत्पादन घाटे की भरपाई की जा सके और अर्थव्यवस्था को समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के साथ मजबूत और सतत विकास के मार्ग पर वापस लाया जा सके।